



10 गांव



01 किलो

सेरेक्ख

76,905.51

+557.45

डॉलर

86.042

-0.285

एक नजर

आदिवासी संगठनों का रांची बंद आज

रांची। रांची के सिरम टोली फ्लाईओवर रैप विवाद को लेकर आदिवासी संगठनों ने 22 मार्च को रांची बंद का अह्वान किया है। इस दिन संगठन के सदस्य सुबह से ही सड़क पर उतरकर चक्का जाम करके राजधानी को बंद करवायेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, अस्पताल संचालकों, दवा दुकान के कर्मियों, एंबुलेंस चालकों और मरीजों को इस बंद से मुक्त रखा गया है।

9 लाख की अफीम व डोडा बरामद, एक गिरफ्तार

मुमला। कामडार पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 9 लाख रुपए मूल्य की अफीम व डोडा बरामद किया है। इस मामले में डुमरटोली कामडार निवासी देशा होरो नामक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एसडीपीओ बंसिया नाजीर अख्तर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डुमरटोली की ओर से एक व्यक्ति तस्करी के इरादे से अफीम लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही कामडार थाना पुलिस ने आरसी चर्च के पास घेराबंदी कर उसे दबाच लिया। उसकी तलाशी लेने पर काले रंग के पिट्टू बैग में 250 ग्राम अफीम बरामद हुआ। फूलाछ के दौरान देशा होरो ने खुलासा किया कि उसने टूरडु जंगल के समीप झाड़ियों में नशीले पदार्थ छुपाकर रखे हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मौके से 7 बरियों में भरा हुआ 53 किलो अफीम डोडा भी बरामद किया। बरामद अफीम और डोडा की कुल कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई है।

व्हाट्सएप से सीधे जुड़ें

1994 से अनवरत हम आपके लिए समाचारों को प्रमुखता की नीति पर कार्य करते रहे हैं। इसे और सुगम बनाने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 72094 53444 पर आप सीधे अपनी परखी हुई सच्ची खबर फोटो सहित सक्षेप में भेज सकते हैं। आपतिजनक बातें भेजने पर आइट्टी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। यदि आपको अखबार की प्रति नहीं मिल पा रही है या वित्तापन देना चाहते हैं तो इस नंबर पर 72094 03444 संपर्क करें।

आज कल

दिल्ली हाईकोर्ट जज के बंगले पर मिले 15 करोड़ कैश

हे राम!

Yash...

इंडिया

एक समय था जब सेवानिवृत्ति पेंशन व परिवार, विशेषकर बच्चों से देखभाल की उम्मीद पर लोग टिके रहते थे कि सब ठीक ठीक होगा पर इधर नौकरी और पेंशन के नियम बदले हैं और साथ ही शहरों में रहने वाले लोग बढ़े हुए खर्च के कारण कई बार मां बाप की चाहकर भी सही देखभाल नहीं कर पाते। आज के दौर में सेवानिवृत्ति एक ऐसा लक्ष्य है जिस पर हम सभी की तैयारी और जानकारी जरूरी है। कामकाजी जीवन में बदलावों को देखते हुए, यह जानना कि कब सेवानिवृत्त होना है, थोड़ी भ्रमित करने वाली बात बन जाती है। रिटायर होने की उम्र तब होती है जब कोई 60 साल का हो जाए। लेकिन ऐसे कई संगठन हैं जो आपको 55 या 58 साल की उम्र में रिटायर कर देते हैं। भविष्य के लिए और आत्मनिर्भर बने रहने के लिए सिद्धांत है कि यदि 65 वर्ष की आयु तक आपके पास वार्षिक वेतन की कम से कम 10 गुना रकम हो, तो यह सहज सेवानिवृत्त के लिए पर्याप्त है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि बचत और निवेश से चार फीसदी की निकासी से 25-30 वर्षों तक बचत पर जीवन जीना आरामदायक होगा। ये दोनों सामान्य नियम नहीं हैं। लेकिन आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए एक अच्छा सकेतक है। चार फीसदी निकासी वाला फंडा इस तथ्य पर आधारित है कि यदि आप केवल उतना ही निकालते हैं जितना अपनी बचत से हर साल कमाते हैं तो आपका धन लंबे समय तक टिका रहेगा। हां, इस गणना में महंगाई पर विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन, आपको एक आईडिया मिलता है कि सेवानिवृत्त फंड से 7-8 फीसदी निकासी पर विचार करना चाहिए। नियमित खर्चों के लिए सेवानिवृत्त फंड से आपात खर्चों को अलग रखें। इसलिए, सेवानिवृत्त में अपने सभी खर्चों और वित्तीय जरूरतों को एक ही टोकरी में डालने के बजाय आपात स्थिति के लिए पैसा अलग रखना चाहिए। सेवानिवृत्त में

राष्ट्रीय नवीन मेल

हर पक्ष की खबर | हर पक्ष पर नजर

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उठा रहे हैं ठोस कदम : मुख्यमंत्री

बीमारियों की पहचान और उसके समुचित इलाज के लिए पूरे राज्य का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाने की है जरूरत

नवीन मेल संवाददाता रांची। जीवन शैली में बदलाव, रहन-सहन, खान-पान, पर्यावरण और जेनेटिक कारणों से आज डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और अस्थमा जैसी कई गैर संचारी बीमारियां (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज) लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। हर घर में कमोबेश ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही है। अगर हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं हुए, तो ऐसी बीमारियां हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रबीन्द्र नाथ महतो की अध्यक्षता में यूनिसेफ की ओर से आयोजित : राउंड टेबल ऑन प्रीवेंटिंग चाइल्डहुड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू



हेल्दी डाइट्स पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। पूरे राज्य का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाने पर जोर : मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तरह-तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही है। ये बीमारियां कैसे और किन लोगों को अपनी चपेट ले रही है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए राज्य स्तर पर हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाने पर विशेष जोर है, ताकि बीमारी का प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव हो

सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है, ताकि लोगों को होने वाली बीमारी की पहचान के साथ उसके समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई ऐसे हिस्से हैं, जहां लोगों में विशेष

तरह की बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती है। सिमडेगा जैसे जिलों में सिकल सेल और एनीमिया जैसी बीमारियां आम है, तो साहिबगंज और संथाल के हिस्सों में कालाजार का प्रभाव ज्यादा है। ऐसी और भी कई बीमारियां हैं, जो क्षेत्र विशेष में विशेष रूप से लोगों को हो रही है। ऐसे में क्षेत्र विशेष तथा वहां व्याप्त बीमारियों को चिन्हित कर उसके समुचित इलाज की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, ताकि

जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक बनती जा रही कैंसर और हृदय रोग जैसी गैर संचारी बीमारियों से बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के साथ खान-पान में हेल्दी डाइट्स के इस्तेमाल एवं ज्यादा से ज्यादा शारीरिक गतिविधियों (फिजिकल एक्टिविटीज) पर फोकस करने की जरूरत है। अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो आगे चलकर ऐसी बीमारियों के इलाज में काफी खर्च करना पड़ सकता है, वहीं पूर्ण स्वस्थ होने की गारंटी भी नहीं दी जा सकती है।

उन इलाकों में रहने वाले लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियां को ऐसी बीमारियों से बचाया जा सके। अपने खान-पान में मिलेट्स का करें उपयोग, जंक फूड्स से रहें दूर : मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नई-नई बीमारियां तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इसके पीछे कहीं ना शेष पेज 11 पर

मंत्री राधाकृष्ण किशोर बेहतर इलाज के लिए गए दिल्ली

सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात



नवीन मेल संवाददाता रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को बेहतर इलाज के लिए शुक्रवार को विशेष विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। इससे पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के स्टेट हेयर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बुधवार को रात वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तबीयत अचानक खराब हो गयी थी। खांसी की शिकायत के बाद उन्हें ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद उन्हें नयी दिल्ली ले जाया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से खराब था। उन्हें खांसी की शिकायत थी। बुधवार को रात सांस लेने में उन्हें

छाती रोग विशेषज्ञ की निगरानी में थे मंत्री

रांची के ऑर्किड अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ओपीडी के छाती रोग विशेषज्ञ डॉ निशीथ कुमार की निगरानी में थे। अस्पताल में एडमिट कराने के बाद उनकी छाती का सीटी स्कैन किया गया था। इसमें हल्का इन्फेक्शन पाया गया था। उन्हें फ्लेमोनोलॉजी विभाग में रखा गया था। इसके बाद आज शुक्रवार को मंत्री विशेष विमान से बेहतर इलाज के लिए नयी दिल्ली रवाना हुए।

काफी तकलीफ होने लगी। खांसी की समस्या काफी बढ़ जाने के बाद मंत्री राधाकृष्ण किशोर को रांची के ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था।

पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर की हत्या

खुद भी फांसी लगा कर किया आत्महत्या

नवीन मेल संवाददाता नावाबाजार। नावाबाजार थाना स्थित इटक पंचायत के बरारी गांव में पति-पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद पति ने स्वयं भी घर से कुछ दूर जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मृतक का नाम उपेंद्र पासवान व मृतका का नाम सूर्यमुखी देवी है। नावाबाजार पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परीजनों को सौंप दिया है। नावाबाजार पुलिस पूरी मामले की



जांच अपने स्तर से कर रही है। बताया जाता है कि उपेंद्र पासवान पति-पत्नी दोनों साथ रिश्तेदारी में गए थे। वहां से गुरुवार को वापस घर लौटे थे। देर रात पति-पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद पति उपेंद्र पासवान ने तांगी से अपनी पत्नी सूर्यमुखी पर हमला कर दिया। जिसमें सिर व गर्दन पर गंभीर चोट लगी। इससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद उपेंद्र कुल्हाड़ी के साथ घर से लगभग एक किलोमीटर दूर खुटीसोत नदी के किनारे एक पेड़ में गमछ के सहारे लटक कर फांसी लगा लिया। दंपति की 2 वर्षीय दुधमुंही बेटी पूरी रात मां के शव के पास रोती-बिलखती अकेले रातभर पानी में भीगी रही। शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों द्वारा स्थिति को देखते हुए तत्काल घटना की जानकारी नावाबाजार पुलिस को दी। इस घटना के बाद से गांव में सन्नता का माहौल है। ग्रामीण कुछ बात करने से करता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले पर अनुसंधान शुरू कर दी है।

अपराधियों के हमले में घायल युवक की मौत आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

नवीन मेल संवाददाता

चतरा। जिला मुख्यालय के मेन रोड स्थित जामा मस्जिद के पास अज्ञात अपराधियों ने अचानक शहर के दिग्भा मोहल्ला पुरैनिया तालाब निवासी अंकित गुप्ता पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसकी रिस्म में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से शहर में तनाव का माहौल हो गया। आक्रोशित परिजनों ने चतरा-गया व चतरा-रांची सड़क को जाम करने के साथ शहर के दुकानों को भी बंद करा दिया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 7-8 युवकों ने पुरानी रजिंश में मारपीट की घटना



को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि मेन रोड स्थित जामा मस्जिद के समीप स्कूटी से घर जा रहे मृतक अंकित पर घात लगाए हमलावरों ने लोहे के रड, फाइटर और चाकू समेत अन्य

धारदार हथियार से अचानक वार कर दिया। इसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद शहर में अफरा-तफरी मच गयी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस गंभीर अवस्था में युवक को सदर अस्पताल में भर्ती करायी। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रिस्म रेफरकर को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि मेन रोड स्थित जामा मस्जिद के समीप स्कूटी से घर जा रहे मृतक अंकित पर घात लगाए हमलावरों ने लोहे के रड, फाइटर और चाकू समेत अन्य

चतरा में जुड़वा बच्चों के साथ आग में जिंदा जली महिला

नवीन मेल संवाददाता

चतरा। जिले में जुड़वा बच्चों के साथ एक महिला आग में जिंदा जल गई। हादसे का कारण पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। मृतका हादसे के वक्त घर पर अकेली थी। उसका पति दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। इस हादसे से गांव में शोक की लहर है। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की घोड़दौड़ पंचायत के करिहारा गांव में शुक्रवार को एक महिला की अपने तीन माह के जुड़वे बच्चों के साथ जलकर मौत हो गई।

महिला करिहारा गांव की दिलीप यादव की पत्नी शिवी देवी (22 वर्ष) थी। घटना की खबर सुनकर गांववाले मृतका के घर पहुंचे। इस हादसे से माहौल गमगीन हो गया था। हादसे की वजह का पता नहीं लग सका है। सूचना मिलते ही पहुंची प्रतापपुर पुलिस : आग में जलकर तीन लोगों की मौत की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, प्रतापपुर पुलिस ने करिहारा गांव पहुंचकर शव का पंचनामा किया और कब्जा में ले लिया। घर पर अकेली थी मृतका : मृतका के परिजनों ने बताया कि

शिवि देवी अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। जब उसके ससुर घर पर आए तो उन्होंने देखा कि बहू और जुड़वा बच्चों का शव पड़ा हुआ है। इसके बाद उन्हें पड़ा जानकारी आसपास के ग्रामीणों को दी। जानकारी मिलते ही ग्रामीण जमा हो गए। इसके बाद हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। दिल्ली में मजदूरी करता है मृतका का पति : मृतका का पति दिलीप यादव दिल्ली में मजदूरी करता है। चार साल पहले उसकी शादी हुई थी। कुछ महीने पहले उसे जुड़वा बच्चे हुए थे।

पारिवारिक शांति के लिए सेवानिवृत्ति की प्लानिंग जरूरी



सभी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए इस आपात खाते में आपके वार्षिक खर्चों के कम से कम 2-3 वर्षों के लिए पैसा अलग रखा जाना चाहिए। यदि रिटायर होने पर आपका वार्षिक खर्च पांच लाख रुपये है तो आपात स्थिति से निपटने के लिए 15 लाख रुपये अलग रखें। इनमें चाहिए। नियमित खर्चों के लिए सेवानिवृत्त फंड से आपात खर्चों को अलग रखें। इसलिए, सेवानिवृत्त में अपने सभी खर्चों और वित्तीय जरूरतों को एक ही टोकरी में डालने के बजाय आपात स्थिति के लिए पैसा अलग रखना चाहिए। सेवानिवृत्त में

करने का लाभ मिल सके। इक्विटी में पैसे लगाने का कारण समय के साथ उसके मूल्य को बनाए रखना है। याद रखें, इक्विटी में भी ऐसे विकल्प हैं जिनमें कम जोखिम होता है। जैसे लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक। यह उनके लिए महत्वपूर्ण है जो पेंशन पर सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें पेंशन आय का एक स्रोत है न कि एकमात्र स्रोत। ब्याज दरें अक्सर कम होने के कारण सेवानिवृत्त के लिए की गई बचत पर्याप्त नहीं हो सकती है। इसलिए, सेवानिवृत्त में अतिरिक्त आय के लिए तैयार रहें और केवल पेंशन पर निर्भर न रहें। आप सेवानिवृत्त में आय के कई साधन बना सकते हैं। पेंशन की रकम को नियमित खर्चों के लिए निवेश कर सकते हैं। इस फॉर्मूलें से महंगाई को मात देने वाले साधन से लाभ उठाने के लिए इक्विटी में निवेश की जाने वाली अतिरिक्त रकम का उपयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास धन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त जगह है, जो महंगाई को मात देती है। सेवानिवृत्ति

में जितना संभव हो सके, उतने वर्षों तक केवल पेंशन पर निर्भर रहने का प्रयास करें। रिटायरमेंट में हेल्थ केयर की लागत तेजी से बढ़ती है। लोग अपनी कंपनी से स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करते हैं, लेकिन यह तब तक ही है, जब तक आप कार्यरत हैं। रिटायर होने से पहले खुद का स्वास्थ्य बीमा लें। सुनिश्चित करें कि इसमें आपकी उम्र 80 वर्ष और उसके बाद तक कवर हो। यदि आप कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, तो संभावना है कि आप रिटायरमेंट बचत को अपनी योजना से अधिक वर्षों तक समाप्त कर देंगे। अगर आपने रिटायरमेंट में खर्च की उपरोक्त पांच बातों को ध्यान में रखा है तो संभावना है कि आप अपने रिटायरमेंट संबंधी खर्चों को आराम से प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी आसानी से उसे स्वीकार नहीं कर पाते और न अपने खर्चों पर रोक लगाते हैं जिससे उन्हें परेशानी होती है। हमें इस बदलाव को मानसिक रूप से स्वीकार करना चाहिए और मान कर चलना चाहिए कि यह जीवन का एक अंग है जिसका स्वागत करना है।

झारखंड विधानसभा में आपस में इरफान और सुदिव्य उलझे

टोकने पर इरफान अंसारी ने कहा- हर बात में फुदकते रहते हैं

नवीन मेल संवाददाता रांची। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब सत्तापक्ष के ही दो सदस्य आपस में उलझ गए और बहस करने लगे। यह घटना उस वक्त हुई जब स्वास्थ्य मंत्री एक कांग्रेस विधायक द्वारा पुछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, इसी दौरान संसदीय कार्यमंत्री ने बीच में खड़े होकर उन्हें ठीक से जवाब देने की सलाह दी तो स्वास्थ्य मंत्री को बुरा लग गया और उन्होंने कहा कि वे हर बात में फुदकने लगते हैं। यह मामला झारखंड सरकार के दो मंत्रियों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और संसदीय कार्यमंत्री व



नगर विकास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार सोनु के बीच का है, जो कि आपस में बहस करने लगे। इस बीच सदन का माहौल पूरी तरह से गरमा गया। दरअसल कार्यवाही के दौरान कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी से सवाल पुछा था। इसके बाद जब अंसारी जवाब दे रहे थे तो नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनु अचानक बीच में खड़े हो तो स्वास्थ्य मंत्री को बुरा लग गया और उन्होंने कहा कि वे हर बात में फुदकने लगते हैं। यह मामला झारखंड सरकार के दो मंत्रियों स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और संसदीय कार्यमंत्री व

न्यूज बॉक्स

विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन भविष्य के वैज्ञानिकों को मिला प्रोत्साहन



लोहरदगा। जे.सी.ई.आर.टी. रांची की वार्षिक कार्ययोजना के अनुरूप डायट चोरी में जिले के 44 माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग 9 के छात्रों के लिए विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य अभिषेक बड़ाईक और अन्य विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। प्राचार्य अभिषेक बड़ाईक ने अपने उद्घोषन में छात्रों को प्रेरित किया और कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने छात्रों को इस प्रकार के कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रदर्शनी में सामाजिक विज्ञान के 44 और विज्ञान के 27 प्रदर्शनों का अवलोकन किया गया और सफल छात्रों को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार के साथ प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रथम दस आने वाले विद्यार्थियों और नोडल शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। प्रतिकूल मौसम के बावजूद प्रतिभागी छात्रों का उत्साह चरम पर था और उन्होंने विभिन्न विषयों पर उत्कृष्ट प्रदर्श प्रस्तुत किए। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना था। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों को अपने विचारों और प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिला, जिससे उन्हें अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नेत्र चिकित्सक ने स्कूली बच्चों के आंखों की जांच की



सेन्हा-लोहरदगा। प्रखंड क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नेत्र चिकित्सक द्वारा आंख जांच किया गया। नेत्र चिकित्सक डॉ। शशि कुमार द्वारा राजकीय मध्य विद्यालय उपर तुरीयडीह में अध्ययनरत 29 छात्र छात्राओं का आंख जांच किया गया। आंख जांच के दौरान आंख से पानी गिरना,आंख में खुजली होना,कम दिखाई देना,आंख में जलन,दूर की वस्तु धुंधलापन दिखाई देना सहित आंख से सम्बंधित विभन्न तरह के बीमारियों का जांच कर इलाज किया गया। जांच के उपरांत सुबह शाम आंख को साफ पानी से धोकर गुलाब जल डालने के लिये बताया गया। साथ ही ताजा फल,हरा साग,अंडा और दूध का सेवन करने और विटामिनयुक्त भोजन करने का निर्देश दिया गया। डॉक्टर के द्वारा आंखों की रोगानी का बचाव के लिये परामर्श देते हुए आंख में जलन,आंख से पानी आना जैसे बीमारियों के लिये निःशुल्क दवा दिया गया। साथ ही छात्र-छात्राओं के बीच दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करा कर सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

पवित्र रमजान माह में तीसरे जुम्मे की नमाज अदा की गई



सेन्हा-लोहरदगा। प्रखंड क्षेत्र के सभी मस्जिदों में पवित्र रमजान माह का तीसरे जुम्मे की नमाज अदा की गई। वही मौलाना और मौलवियों ने रमजान के बारे में बताते हुए कहा रमजान के महीना नसीब वालों को मिलती है। जिसे सभी लोगों को दिल से अल्लाह को याद कर रोजा रखना चाहिए जिसे बरकत होता है। रमजान में हर मुसलमानों को आपस में मिलजुल कर घर परिवार तथा आस पड़ोस में खुशियां बांटना चाहिए और रमजान में असाहय और गरीबों का अधिक से अधिक मदद करना चाहिये तथा रमजान में जुम्मे की नमाज अदा कर घर परिवार तथा क्षेत्र में अमन चैन के लिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए जिसे सभी लोग शांति और सुकून से जी सके वही जगह जगह पर मस्जिदों में कुराने पाक की तिलावत कर नमाजे तरावीह अदा की जा रही है। बहुत से जगहों पर कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया गया है। साथ रमजान माह में मुस्लिमों के लिये अल्लाह द्वारा फरमाया गया। विभिन्न बातों को बताया गया। वही प्रखंड क्षेत्र के सैरंगहातु, उगरा, चितरी डांडू, सेन्हा, अरु, कल्हेपाट, भड़गां, झखरा, अरु बांधटोली, तोड़ार, भण्गाडी सहित सभी जगहों के मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा एक साथ अमन चैन से शांति पूर्वक रमजान माह के तीसरे जुम्मे की नमाज अदा की गई।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला समिति लोहरदगा की बैठक



लोहरदगा। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला समिति लोहरदगा द्वारा आयोजित बैठक में जिले के विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक और अजट्टा के संघीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्रेड 03, 04 व 07 में प्रोन्नति और सेवानिवृत्त लाभ शामिल थे। बताया गया कि जिले में ग्रेड 3 की प्रोन्नति एक लम्बे समय से बाधित है। वही लगभग 30-35 वर्षों से जिले में बाधित इस ग्रेड की प्रोन्नति का रास्ता पिछले वर्ष ही साफ हो चुका है। बार-बार के विभागीय उच्चाधिकारियों के द्वारा निर्देशित करने के उपरान्त भी इस जिले में सेवानिवृति की तिथि को सम्माना उनके पावना का लाभ नहीं दिया जा पा रहा है। वही मध्याह्न भोजन में राशि एवं चावल का आवंटन मामले में जिले के अनेक विद्यालयों में राशि समाप्ति या ऋणायामक स्थिति में रहने पर भी प्रत्यक्ष रूप से माता समिति परन्तु परोक्ष रूप से शिक्षकों पर मध्याह्न भोजन हराहाल में जारी रखने का दवाब रहता है। इस सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी बिन्दुओं पर सुधार हेतु आश्वासन दिए। मौके पर अजट्टा जिलाध्यक्ष मणी उरांव, महासचिव शंभु कुमार शर्मा, कार्यालय सचिव विजय कुमार दास सहित प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह भी शामिल थे।

भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद

नवीन मेल संवाददाता
सेन्हा-लोहरदगा। प्रखंड क्षेत्र में लगातार हो रहे तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों का फसल हुआ। ओलावृष्टि के कारण सब्जी,दलहन तिलहन फसलों के साथ-साथ रबी फसल काफी बर्बाद हो गया। टमाटर, बैंग, फ्रेंचबीन, खीरा सहित विभिन्न सब्जियां बर्बाद हो गया। साथ ही तेज हवा चलने के कारण पेड़ गिरने से प्रखंड क्षेत्र में खपरेल मकान को भी भारी क्षति पहुंची है। ओलावृष्टि से आम में लगे मंजर व फल भी झड़ कर नष्ट गया।जिसे नष्ट फसलों को देख किसान रोना आ रहा हैं। ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा तबाही प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत के गांवों में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वही भयंकर ओलावृष्टि होने के कारण सड़क और खेत खलिहानों में उजले चादर सी परत जम गया था। साथ ही बारिश के कारण सभी जगहों में जलजमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। जगह जगह नाली में जलजमाव के कारण घरों के अंदर पानी प्रवेश कर गई। आंधी तूफान और ओलावृष्टि से अरहर, चना, सरसों, तोसी, टमाटर, बैंगन, खीरा, लहसुन, प्याज, तरबूज और आम, गेहूं का फसल को भी अधिक नुकसान हुआ है। पत्थर की मार से

आम का मंजर झड़ कर नष्ट हो गया। साथ ही अरहर, चना, सरसों का फूल व फल ओलावृष्टि से झड़ कर बर्बाद हो गया।वही किसानों का कहना है। कि प्रत्येक वर्ष किसानों की फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हो रही है। वही जिला कृषि पदाधिकारी सालेन खलखो और अंचलाधिकारी मोदत्सर नजर

लोहरदगा पुलिस को मिली बड़ी सफलता डकैती की घटना का खुलासा पांच अपराधी हुए गिरफ्तार



नवीन मेल संवाददाता
लोहरदगा। लोहरदगा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गत 19 मार्च को हुई डकैती की घटना का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आये अपराधियों में प्रीतम कुजूर, पंकज उरांव, विष्णुकान्त उरांव, विवेक बखला और सिद्धार्थ चौक बड़ाईक उर्फ बादल शामिल हैं। सभी अपराधी गुमला जिला के निवासी हैं और उनका अपराधिक इतिहास है। इस संदर्भ में डीएसपी समीर कुमार तिरकी ने पत्रकारों को बताया कि 19 मार्च को सेन्हा थाना क्षेत्र के कंडरा कोराम्बे पथ में घटना हुई थी। अपराधियों ने जगत उरांव और उनकी पत्नी से दो मोबाईल फोन, एवं पर्स छीन लिया, जिसमें एटीएमकार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, चाँदी का एक जोड़ा पायल, चाँदी का एक चैन तथा 200 रूपया रखा हुआ था। इस घटना के संबंध में सेन्हा थाना काण्ड संख्या- 35/25 दि०-20.03.25 धारा- 310 (2) बीएनएस अंकित किया गया है। काण्ड के अनुसंधान के क्रम में

आसमानी बिजली की चपेट में आकर एक की मौत, दो घायल

कुड़। कुड़ के जामड़ी तालाब के पास गुमराव की रात बारिश के साथ हुए वज्रपात में एक कि मौत हो गयी जबकि दो लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान जामड़ी गांव निवासी तुलु उरांव के रूप में हुई है। तुलु उरांव 58 वर्ष अपना होटल बंद कर सार्डकिल से रात्रि करवा 7:30 बजे वापस घर जा रहा था तभी वज्रपात की चपेट में आ गया। बुरी तरह झुलस चुके तुलु उरांव को कुड़ सिप्लेससी लाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वही वज्रपात की इस घटना में टाकू गांव निवासी 14 वर्षीय अर्जुन उरांव एक बाइक सवार व्यक्ति भी जख्मी हो गया।

लोहरदगा में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भव्य आयोजन विद्यालय विकास में अभिभावकों की भागीदारी को भी बढ़ावा

नवीन मेल संवाददाता
लोहरदगा। लोहरदगा के पीएम श्री राजकीय कृत मध्य विद्यालय नवाडी पाड़ा में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय विकास में अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ावा देना था।विद्यालय के प्राचार्य अरुण राम ने बताया कि अभिभावकों की भागीदारी से विद्यालय उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। जन भागीदारी से बच्चों की उपस्थिति में सुधार हुआ है और नैतिक शिक्षा का महत्वपूर्ण हो रहा है।



लोहरदगा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश

लोहरदगा। लोहरदगा में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने की। इस बैठक में वज्रपात और सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों और पशुओं के मामलों पर चर्चा की गई और प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, जिले में भारी बारिश और ओला वृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान पर भी चर्चा हुई और किसानों को मुआवजा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए। वज्रपात से मृत चार व्यक्तियों, एक पशु, सड़क दुर्घटना में मृत नौ मामलों पर समिति के सदस्यों के संग चर्चा की गई और मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को दिया गया। बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुण्डा, अनुमण्डल पदाधिकारी अमित कुमार, एसडीपीओ श्रद्धा केर-केट्टा, सिविल सर्जन डॉ शंभूनाथ चौधरी, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रमोद दास, नगर पर्वट कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी शिवनंदन बड़ाईक समेत अन्य उपस्थित थे।

मंसूरी अंचल क्षेत्र का भ्रमण कर फसलों का जायजा लिया और किसानों को बताते हुए कहा कि उचित मुआवजा प्राप्त के लिये किसान आवेदन के साथ जमीन का रशीद, नुकसान फसल का फोटो, आधार कार्ड, जमीन मालिक का वंशावली, बैंक पास बुक का जेरोक्स अंचल कार्यालय में जमा

जेएनवी जालना के विद्यार्थियों ने डीसी से की मुलाकात, कॉरियर के अवसरों पर की चर्चा



नवीन मेल संवाददाता
लोहरदगा। लोहरदगा में महाराष्ट्र राज्य के जालना जिला के परतूर शहर में अवस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण से मुलाकात की और जिला प्रशासन के कार्यों और सिविल सेवा की तैयारी के बारे में जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने छात्रों को अपने करियर का चयन करने और अनुशासित होने के महत्व को बताया। उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी में दसवीं, 12वीं और स्नातक की शिक्षा की महत्ता को भी बताया। उपायुक्त ने छात्रों को यह भी बताया कि स्कूली जीवन के बाद सिविल सर्विस की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को अपने विषयों का चयन करना चाहिए और स्नातक में अच्छे कॉलेज में नामांकन लेने से बेहतर परिवेश मिलता है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राधानाचार्य एसी झा, दो शिक्षिकाएं और 23 छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। छात्र-छात्राओं ने उपायुक्त को स्मृतियां भेंट की और अपने लोहरदगा प्रवास के अनुभव

पुलिस ने एफसीआई मार्का बोरा में लोड एक ट्रक चावल पकड़ा, जांच जारी, कालाबाजारी का संदेह

कुड़। कुड़ पुलिस ने शुक्रवार को एनएच 75 कुड़-चंदवा रोड पर एक 709 मालवाहक ट्रक को पकड़ा, जिसमें एफसीआई मार्का बोरे में चावल भरा हुआ था। पुलिस को आशंका है कि यह चावल कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था, क्योंकि चावल भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड के बोरे में भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचित किया, जिसके बाद विभाग के कर्मि थाने पहुंचे और वाहन से बरामद कागजात की जांच की। हालाँकि, मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 709 मालवाहक ट्रक में एफसीआई का चावल कुड़ के रास्ते रांची की तरफ जा रहा है। पुलिस ने वाहन जांच अभियान शुरू किया और रजगुरुवा के नजदीक ट्रक को रुकवाकर चालक से कागजात की मांग की। चालक टायलेट के बहाने पुलिस को चकमा देकर भाग गया, जिससे यह संदेह और पुख्ता हो गया है कि चावल कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस और आपूर्ति विभाग की जांच जारी है, और अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि चावल गरीबों के बीच वितरण के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग से मिला था या नहीं। कुड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि चावल लदा ट्रक पकड़ा गया है और ट्रक कुड़ थाना के संरक्षण में है।

ओलावृष्टि और वज्रपात से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा: सीओ

कुड़। कुड़ सीओ मशूरी मिश्रा ने विज्ञप्ति जारी कर प्रखंड में 20 से लेकर 21 मीर्व तक जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि से व्यापक पैमाने पर बर्बाद हुई फसलें, मकानों को पहुंचे नुकसान और वज्रापत से हुई जान माल की क्षति के मुआवजे की प्राप्ति हेतु अवाल अधिकारी के नाम आवेदन के साथ लगान रशीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फोटो के साथ खेतों में खड़े होजर तीन दिशाओं से ली गयी फोटो, मकान क्षतिगास्त हुआ है तो उसकी फोटो को मुखिया से अनुवृत्ता करा कर अवाल कार्यालय में जट्ट से जल्ट जमा करने की अपील की है।

करने का निर्देश दिया गया। वही किसानों का कहना है। अंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार या प्रशासन की ओर से मुलावजा नही मिलने पर क्षेत्र के किसान बर्बाद हो जायेंगे। प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार सुबह में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने से दलहन, तिलहन, सब्जी और आम का खेती को काफी नुकसान हुआ है। जिसे किसान लाचार और बेबस हो गये हैं।

साझा किए। सभी छात्र-छात्राओं को कल्चरल एक्सचेंज एवं नेशनल इंटीग्रेटी प्रोग्राम के तहत एक वर्ष के लिए कक्षा नौवीं की पढ़ाई के लिए हिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यालय अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय जोगना में भेजा गया था जो इसी माह पूरा हो जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अपने करियर का चयन करना और विद्यार्थी जीवन में उसके लिए अनुशासित होना बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह समय से उठना, व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना आवश्यक है। स्कूली जीवन के बाद सिविल सर्विस की चाह रखने वाले विद्यार्थियों को उसी के अनुसार अपने विषयों का चयन करना चाहिए। स्नातक में अच्छे कॉलेज में नामांकन लेने से बेहतर परिवेश मिलता है जिससे यूपीएससी परीक्षाओं में बहुत मदद मिलती है। उपायुक्त चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों के बारे छात्र-छात्राओं को जानकारी दी। उपायुक्त ने मराठी भाषा में छात्र-छात्राओं को करियर टिप्स दिये। छात्र-छात्राओं की ओर से उपायुक्त को स्मृतियां भेंट की गई। साथ ही, अपने लोहरदगा प्रवास के अनुभव भी साझा किए।

लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के पत्रकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना गौरव की बात : सुखदेव भगत

लोहरदगा। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र गुमला के पत्रकार अमरनाथ कश्यप एवं कामडरा प्रखंड के पत्रकार शहाब अली को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया। इन दोनों पत्रकारों ने झारखंड के गुमला जिले के कामडरा प्रखंड के नावाडीह गांव की एथलीट आशा किरण बारला की चुनौतियों पर स्टेरी की थी। यह अवार्ड इन्हें खेल पत्रकारिता के श्रेणी में मिला है।नई दिल्ली में लोहरदगा लोकसभा के माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत ने दोनों पत्रकारों से मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। सांसद सुखदेव भगत ने दोनों पत्रकारों को राष्ट्रीय अवार्ड मिलने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि यह झारखंड के लिए काफी गौरव की बात है उन्होंने यह भी कहा कि लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के दो कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों का दिल्ली में सम्मानित किया जाना राज्य के अन्य पत्रकारों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। सांसद श्री भगत वेस्टर्न एवेन्यू में उनसे मुलाकात किया और यह भी कहा कि एक साधारण शहर के असाधारण पत्रकार को देश के सर्वोच्च मंच पर सम्मानित होते देखना न केवल हृदय को गर्व से भर देने वाला था। बल्कि वह क्षण उन सभी के लिए प्रेरणा और उम्मीद का प्रतीक बन गया जो पत्रकारिता को समाज का दर्पण बनाने में जुटे हैं, यह क्षण एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद किया जाने वाला क्षण रहा।

	झारखण्ड सरकार कार्यालय: जिला मत्स्य पदाधिकारी, लोहरदगा। (समाहण्णालय परिसर लोहरदगा, ई-मेल- dfojhar2011oh@gmail.com)
	आवश्यक सूचना कार्यालय झापांक 183 दिनांक 06.03.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत जाल/हापा की आपूर्ति हेतु अत्यकालीन निविदा आमंत्रण की सूचना PR No. 348022 Lohardaga (24-25)#D द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें निविदा की निर्धारित तिथि 22.03.2025 को अपरिहार्य कारणवश अगले आदेश तक के लिए स्थगित की जाती है। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदगा। PR 348954 (Lohardaga) 24-25 (D)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PLANNING AND INVESTIGATION DIVISION ROAD CONSTRUCTION DEPARTMENT (RCD), RANCHI Nirupan Bhawan, 3rdFloor, Room No. 401, 56-Set Doranda, Ranchi-834002	
e-Procurement (Short Tender Notice) Letter of Invitation (LOI) No-20/2024-25 (1st Call) e-Tender Ref No:-RCD/PID/RANCHI/20/2024-25 Date:-21.03.2025	
1	Name Of Work Consultancy Services for Preparation of Feasibility Study Report to ease the Traffic System of Redma Chowk,Dalonganj situated at junctionof Dalonganj-Lesliganj-Panki (SH 10) and NH-75 in Palamu District in State of Jharkhand. *Only Empanelled consultant with RCD under category-I vide letter No. 3063(S) Ve Dated 22.08.2022are allowed to bid.
2	Tentative Length To be determined by consultant
3	Period of Completion of Work 30 Days
4	Cost of Tender documents& Earnest Money Deposit Cost of tender documents is Rs. 5009/(Non-Refundable) EMD- The quotations have to deposit a fixed amount of Rs 20000.00 (Twenty thousand only) as Earnest Money. As per the Departmental Letter no-4652(S) dated 06.10.2023, cost of tender document and Earnest Money Deposit will be received in online mode only through e-procurement.gov.in) by internet banking/NEFT/RTGS facility as per Standard Operating Procedure (SOP) issued by Information Technology & e-Governance Department, Government of Jharkhand vide letter no- 120 dated 03.10.2023.
5	Mode of Bid Submission e-tendering(https://jharkhandtenders.gov.in/)
6	Date/Time of Publication of Tender on Website 24.03.2025,10:30 AM
7	Online Last Date/Time of Bid Submission 08.04.2025, 17:00 PM
8	Date and Time of Bid opening 09.04.2025, 17:30 PM
9	Bid validity 120 days
10	Designation and Contact no. of Tender inviting Officer Executive Engineer, Planning and Investigation Division,RCD,Ranchi, Mob No.-9471650883
Note:- Only e-Tender shall be accepted. Further details can be seen on e-procurement portal (https://jharkhandtenders.gov.in/). Executive Engineer, Planning & Investigation Division, Road Construction Department, Ranchi PR 348943 Road (24-25)_D	

कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, लोहरदगा

अति अल्पकालीन निविदा

लोहरदगा जिलान्तर्गत जाहेरस्थान, सरना स्थल आदि के लिए पूजन सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दिनांक – 28.03.2025 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, लोहरदगा में मुहरबंद निविदा आमंत्रित किये जाते है। निविदा उसी दिन अपराहन 3:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्रियों की सूची तथा निविदा की शर्तें लोहरदगा जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.lohardaga.nic.in कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, लोहरदगा के सूचना पट्टा पर देखा जा सकता है।
परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, लोहरदगा

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, चतरा। (जिला आपूर्ति शाखा) (e-Mail id:-dso.chatra@jharkhandmail.gov.in)	
--	--

–आम सूचना:–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक–29.01.2025 को आहुत विभागीय Video Conferencing में निदेश प्राप्त है कि सभी राशन कार्डधारियों का आधार नम्बर को संबंधित डीलर के e-Pos मशीन के माध्यम से शत–प्रतिशत् UID Seeding किया जाना है। आधार सीडिंग की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात् जिन कार्डधारियों का e-KYC और UID Seeding नहीं किया जाएगा, वैसे कार्ड धारियों का आवंटन भविष्य में बंद हो जाएगी। सभी PHH/AAV एवं ग्रीन कार्डधारी, अपना एवं अपने परिवार के सभी सदस्य का नजदीकी डीलर के पास जा कर e-KYC और UID Seeding दिनांक–31.03.2025 तक अनिवार्य रूप से करायेंगे।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
PR 348890 (Food Public Distribution and Consumer Affairs) 24-25 (D) चतरा।

गुमला में दो दिनों की अचानक बारिश व ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त-व्यस्त

► **कृषि फसलों और बागवानी पर कहर, कई घरों व पेड़ों को नुकसान, प्रभावितों ने मुआवजे की मांग की**

नवीन मेल संवाददाता
गुमला। जिले में बीते दो दिनों से अचानक बदले मौसम ने कहर बरपाया है। तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं किसानों की फसल पर भारी तबाही मचाई है। इस अप्रत्याशित मौसम ने खरीफ फसलों के साथ-साथ बागवानी फसलों जैसे आम, लीची को भी गंभीर क्षति पहुंचाई है। जिले



के कई गांवों में किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है किसानों की मानें तो तैयार खड़ी धान की फसल, मक्का, अरहर समेत कई प्रमुख फसलें ओलावृष्टि और तेज हवाओं के चलते जमीन पर बिछ गई हैं। वहीं बागवानी में आम और लीची के बागानों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई बागानों

में फलों से लदे पेड़ धराशायी हो गए, जिससे किसानों को लाखों रुपये की क्षति होने का अनुमान है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के कारण कई कच्चे मकान ढह गए तो कहीं पेड़ उड़कर घरों और रास्तों पर गिर पड़े। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी

बाधित रही। प्रभावित क्षेत्रों में लोग दहशत में हैं और शासन-प्रशासन से त्वरित राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गांव रजनटोली, कुरुमगढ़, चैनपुर, बिशुनपुर और घाघरा प्रखंड के किसानों ने बताया कि उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। किसान बबलु उरांव ने बताया, धान की फसल कटाई के लिए तैयार थी। अचानक ओलावृष्टि से पूरा खेत बर्बाद हो गया। अब परिवार का भरप-पोषण कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्राकृतिक

आपदा से हुए नुकसान की भरपाई बिना सरकारी सहायता के संभव नहीं है। पीड़ित परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। किसानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए, ताकि उन्हें इस संकट की घड़ी में सहारा मिल सके। किसानों ने ऋण माफी की भी मांग उठाई है, क्योंकि मौसम की मार से कर्ज चुकाना अब नामुमकिन हो गया है।

सदर अस्पताल में दलालों की सक्रियता पर उपायुक्त सख्त प्रबंधन से स्पष्टीकरण तलब, वेतन अवरुद्ध

नवीन मेल संवाददाता
गुमला। सिलाफारी गांव की एक गर्भवती महिला से जुड़े मामले ने गुमला सदर अस्पताल में दलालों की सक्रियता को उजागर कर दिया है। मामले में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने गंभीर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही आदेश जारी करते हुए कहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अस्पताल प्रबंधक का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, सिलाफारी की एक गर्भवती महिला को गुमला सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने



रिस्म, रांची रेफर किया था। लेकिन बीच में कुछ बिचौलियों ने महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस पूरे प्रकरण में दलालों की भूमिका के साथ-साथ सदर अस्पताल के चिकित्सकों व कर्मचारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि यह मामला गरीब मरीजों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। सदर अस्पताल में दलालों की सक्रियता और चिकित्सकों-कर्मचारियों की निगरानी में हिलाई, प्रशासनिक लापरवाही को

क्या है आदेश में
► 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया।
► असंतोषजनक जवाब मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई।

दशाती है। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि मरीजों को सस्ता, सुलभ और सुरक्षित इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आंधी तूफान ने मचाई तबाही कोटामाटी में उड़ आधा दर्जन घर के एस्बेस्टर

नवीन मेल संवाददाता
घाघरा। गुरुवार को आए तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के वजह से घाघरा प्रखंड के कोटामाटी गांव में लगभग आधा दर्जन से अधिक घर आंधी और बारिश में आने से क्षतिग्रस्त हो गया जिससे पीड़ितों का लाखों का नुकसान हुआ। गुरुवार को करीब 4:00 बजे जोरदार आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई जिसमें कोटामाटी गांव निवासी सलमी देवी का एस्बेस्टर उड़कर टूट गया जिससे उनको लगभग बीस हजार रूपए का नुकसान हुआ वहीं चतु उरांव का घर का एस्बेस्टर घर उड़कर दूसरे दीवार पर जा गिरा जिससे उस घर का भी एस्बेस्टर भी टूट गया और बड़े बोरी में रखा हुआ तीन बोरा धान भीग गया जिससे उनको करीब एक लाख दस हजार



रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कोटामाटी के ही दशरथ लोहरा का एस्बेस्टर उड़ गया जिससे उसको पैंतीस हजार रूपए का लगभग

नुकसान हुआ है।
पीड़ितों का छलका दर्द प्रखंड प्रशासन से तत्काल सहयोग की आस
आंधी से घर का एस्बेस्टर उड़ जाने से पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा और पीड़ितों के आंखों में आंसू और सहयोग की आशा एकदम झलक रहा था। पीड़ित चेतु उरांव ने बताया कि उसके पास मेहनत से उगाया हुआ जितना भी अनाज था वह खराब हो गया है और सर से छत भी चला गया है अब ना रहने के लिए जगह बचा ना ही खाने के लिए अनाज , सुबह में पड़ोसियों ने भोजन पानी का व्यवस्था किया। वहीं अब उनको प्रशासन से ही सहयोग की आस है नहीं तो अब भूखे गुजारा करना पड़ेगा।

बे मौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई ग्रामीणों के घरों के छतों को हुआ नुकसान

नवीन मेल संवाददाता
सिसई (गुमला)। सिसई प्रखंड के विभिन्न गांवों में गुरुवार देर शाम और शुक्रवार की सुबह तेज आंधी तूफान, बारिश के साथ हुई भारी ओलावृष्टि के कारण सैकड़ों किसानों की फसल पुरी तरह से बर्बाद हो गई साथ ही क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों के मकान व एस्बेस्टस को नुकसान हुआ है। लोहरदगा जिले से सटे प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र के बोण्डो, सुरसा, मादा, पुसो, गढ़वाली, भुरसो, छारदा सहित दर्जनों गांव-टोलों में शुक्रवार की सुबह करीब साढ़े नौ बजे आई ओलावृष्टि व बारिश से खेत में लगी तैयार फसलें गेहूं, टमाटर, प्याज, गोभी, भिंडी, करेला, कद्दू, बोदी, बीन सहित ढेरी साग सब्जियों की खेती को भारी नुकसान हुआ है।



जिससे किसानों में भारी हताशा हुआ है।और किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। बोण्डो-मादा के किसान रविराम उरांव ने बताया कि डेढ़ एकड़ से अधिक जमीन पर गेहूं और दो एकड़ में तरबुज का फसल लगाया जा, जो सभी तैयार हो चुके थे, लेकिन बे मौसम हुए बारिश और ओलावृष्टि से पूरा फसल बर्बाद हो गया। खेती में निवेश किये सारी जमा

पूंजी खत्म होने से जीविका पर भारी संकट गहरा गया है। वहीं कुशल टोपो, एतवा उरांव, बुद्धेश्वर उरांव, सुकरा उरांव, चरकु उरांव, शंकर उरांव, छोटेदाला उरांव,बालक टाना भगत, परदेश बेलास तिकी, सुनिल उरांव तेम्बा उरांव सहित कई किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सभी किसानों ने प्रशासन से क्षति पुर्ती और मुआवजा की मांग की है।

चैनपुर प्रखंड में मौसम ने बिगाड़ा हाल जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त

नवीन मेल संवाददाता
चैनपुर। चैनपुर प्रखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी अर्रेंज अलर्ट के प्रभाव से शुक्रवार को आंधी-तूफान और ओलावृष्टि के साथ जनप्रतिनिधियों और प्रखंड कर्मियों को बार-बार सूचना दी गई, परंतु स्थिति अब तक जस की तस बनी हुई है। यह आमजन के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी खतरा बढ़ गया है। दुकानदार सुभाष केशरी ने कहा, हमने कई बार जन प्रतिनिधियों से इस समस्या के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें रोज इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है।चैनपुर प्रखंड के लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही नाली की सफाई और मरम्मत नहीं हुई, तो उनकी दैनिक जीवनशैली पर इसका गंभीर असर पड़ेगा।

गंदगी सड़क पर बहने लगी है। इससे उत्पन्न दुर्गंध से आम जनता और दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। इस नाली की सफाई एवं मरम्मत के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रखंड कर्मियों को बार-बार सूचना दी गई, परंतु स्थिति अब तक जस की तस बनी हुई है। यह आमजन के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी खतरा बढ़ गया है। दुकानदार सुभाष केशरी ने कहा, हमने कई बार जन प्रतिनिधियों से इस समस्या के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें रोज इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है।चैनपुर प्रखंड के लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही नाली की सफाई और मरम्मत नहीं हुई, तो उनकी दैनिक जीवनशैली पर इसका गंभीर असर पड़ेगा।

केन्द्रीय विवि झारखंड में भाषा व स्वदेशी आवाज पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पद्मश्री अशोक भगत रहे मुख्य अतिथि



नवीन मेल संवाददाता
गुमला। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड में भाषा और स्वदेशी आवाज की राजनीति विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। उद्घाटन सत्र में विकास भारती बिशनपुर के सचिव एवं पद्मश्री अशोक भगत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने स्वदेशी भाषाओं और सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय भाषाएं ही किसी समाज की आत्मा होती हैं और इन्हें संरक्षित करना समय की मांग है। इस अवसर पर प्रज्ञा प्रवाह के वरिष्ठ अधिकारी रामाशीष, केन्द्रीय

बैंकर्स की बैठक, केसीसी, एसएचजी जैसी योजनाओं की गहन समीक्षा ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाने पर दिया जोर

नवीन मेल संवाददाता
गुमला। जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न सरकारी बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के उद्देश्य से आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) गुमला, जेएसएलपीएस प्रतिनिधि, जिला उद्यमी समन्वयक सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।

बैठक में उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
लोको बैंक सिसई की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
बैठक में केसीसी योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लोको बैंक सिसई शाखा के प्रदर्शन पर असंतोष जताते हुए लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण सुविधा समय पर मिलनी चाहिए



ताकि वे खेती-किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें।
बीसी सखी योजना को गति देने का निर्देश
ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए उपायुक्त ने फोमेल बैंकिंग करिस्पोण्डेंट (बीसी सखी) की नियुक्ति को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। उन्होंने बैंक प्रबंधकों से कहा कि वे बीसी सखी चयन और प्रशिक्षण में सहयोग करें, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के साथ-साथ ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी समय पर मिल सके। बीसी पॉइंट्स की संख्या बढ़ाने और मौजूदा बीसी पॉइंट्स को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया गया।
एसएचजी महिलाओं को कारोबारी मॉडल में ढालने की पहल
उपायुक्त ने बैठक में एसएचजी

समूहों की महिलाओं के आज्ञीचिका उपक्रमों को बड़े व्यवसाय में बदलने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि महिलाओं को किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के रूप में संगठित कर उन्हें बड़े स्तर पर मार्केटिंग और उत्पादन की दिशा में प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि एफपीओ गठन में गुणवत्ता और दक्षता का ध्यान रखा जाए।
पीएमईजीपी में दस्तावेज प्रक्रिया को सरल बनाने का आदेश
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में दस्तावेजीकरण और ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के निर्देश उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को मिले, यह सुनिश्चित

करना सभी की जिम्मेदारी है।
प्रशासन और बैंकों में बेहतर समन्वय पर बल
बैठक के अंत में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
अस्पताल प्रबंधक का वेतन आदेश तक अवरुद्ध
जिले में मचा हड़कंप इस कार्रवाई के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन समेत स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा है कि मरीजों की अनदेखी और दलालों की भूमिका को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED

(CIN: U40108JH2013SGC001704)

OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, TRANSMISSION ZONE-IV, MEDININAGAR Bypass Road, Sudna, Near Sinchai Vibhag, Medininagar – 822101, Jharkhand, e-mail : gmtz4nig@gmail.com

E- Tender Notice
e-NIT No.-577 /PR/ JUSNL/ 2024-25
E- Tender is invited in two parts i.e. Technical Part (Part-I) and Price Part (Part-II) from reputed, capable, experienced and financially sound firm / agency / contractor for the following work:-

Name of Work	Outsourcing of manpower (Highly skilled/ skilled/ITI trained and Unskilled Khasai/ supporting staff) for operational work at 132.25 kV Railway TSS Nagar Untari for the period from 01.05.2025 to 31.03.2026.
Period of Work	01.05.2025 to 31.03.2026.
Tender fee (Non-refundable)	Rs. 5,900.00/- (Rupees Five Thousand and Nine Hundreded) only.
Earnest Money Deposit	Rs. 75,400.00/- (Rupees Seventy Five Thousand and Four Hundreded) only.
Availability of Tender Documents on e-tender website	From 24.03.2025 at 03.00 PM to 13.04.2025 upto 4:00 PM.
Start Date and time of upload of BID	24.03.2025 at 03:00 PM
End date and time of upload of BID	13.04.2025 upto 04:00 PM
BID Opening date for Technical Part (Part-I)	14.04.2025 at 04:00 PM
BID Opening date for price part	Will be communicated later on.
Tender Inviting Authority and address for communication	General Manager, Transmission Zone-IV, Medininagar, Bypass Road, Sudna, Near Sinchai Vibhag, Medininagar – 822101, Jharkhand.

1. e-Tender document and BOQ including terms & conditions, tender specification can be downloaded from website <http://jharkhandtenders.gov.in>. Any details / clarification required in this regard can also be obtained from the office of the undersigned during office hours. Please contact 7488012827 for any enquiry.
2. The bids will be received through electronic tendering mode only.
3. Bidder shall submit tender fee & EMD as mentioned above through online mode as per rules of e-tendering portal.
4. If there is sudden announcement of holiday by Govt. or Nigam on the date of opening of tender/ last date of submission of bid then the next working day will be considered.
5. No claim shall be entertained on account of disruption of internet services being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last minute technical snag.

सहित एवं राष्ट्रपति में कर्ज बर्दाई। कृपया अपनीचिकित्सा को 18003458570(कॉल सेन्टर) पर दर्ज करायें।
PR 348981 Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd(24-25).D Transmission Zone-IV, Medininagar

संपादकीय

सपनों के घर के नाम पर धोखाधड़ी

मुकदमेबाजी में फंसे हजारों घरों के खरीदारों से सहानुभूति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने बैंकों और बिल्डरों के सांठगांठ की सीबीआई जांच कराने की बात कही है। सीबीआई जांच के अंजाम को समझने के लिए चीफ जस्टिस की अदालत में चल रहे दूसरे मुकदमों का हाल जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के अनुसार, हाई इजार से ज्यादा हाई प्रोफाइल मामलों की जांच पांच साल से और 3,500 मामलों की जांच करीब 10 साल से सीबीआई के पास लंबित है। छह साल पहले जारी नोटिस के बावजूद सीबीआई और सीबीसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर नहीं किया। घर खरीदारों की समस्याओं के समाधान और बिल्डरों के कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 में रेरा का गठन किया गया था, लेकिन अदालतों में बढ़ रहे मामलों से साफ है कि अधिकार राज्यों में रेरा अपने मकसद को पूरा करने में विफल रही है।सिस्टम से हताश और मुकदमेबाजी से परेशान घर खरीदारों की समस्याओं का मूल कारण समझकर ही उनका निवारण हो सकता है। दो साल पहले गठित अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से जुड़े सभी पक्षकारों का विवरण शामिल है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अनुसार, पूरे देश में फंसे हुए दो तिहाई से ज्यादा प्रोजेक्ट एनसीआर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में हैं। सीएजी की पुरानी रिपोर्ट में नोएडा में बिल्डर, अफसर और नेताओं के गठजोड़ का विस्तार से खुलासा है। उसके अनुसार, वर्ष 2005 से 2018 के बीच सिर्फ तीन बिल्डरों की 80 फीसदी वाणिज्यिक प्लॉट का आवंटन हुआ था। उन कंपनियों से 14,958 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया वसूलने में नोएडा के अधिकारी विफल रहे। उनमें से एक कंपनी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने ईडी की जांच कराने की बात कही है।अफसरों और बिल्डरों के भ्रष्ट गठजोड़ के और भी कई आगम हैं। ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों के साथ मिलकर तीन गांवों में 2,000 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कॉलोनी और विला बनवा दिए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ऐसे प्रोजेक्ट्स में अफसर और बिल्डर मिलाई हजम करके निरीह जनता को अदालतों के चक्कर काटने के लिए अभिशप्त कर देते हैं। घर खरीदारों की याचिका के अनुसार, डेवलपर्स की देरी के चलते उन्हें प्लैट का कब्जा नहीं मिला, लेकिन ईएमआई के भुगतान के लिए बैंक उन्हें मजबूर कर रहे हैं। बैंकों के वकील के दावे के अनुसार, दिवालिया हो रहे बिल्डरों के लिए बैंकों की जवाबदेही नहीं है। इस पर जजों ने सवाल पूछा कि साइट पर एक ईंट भी नहीं, तो फिर बैंकों ने 60 फीसदी लोन कैसे दे दिया। इस पूरे मामले की तह में जाने पर घर खरीदारों के साथ देश के खजाने को लप रही चपत को समझा जा सकता है। वित्त मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में 16.35 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बढ़े खाते में डाला गया है।

सीबीआई जांच के अंजाम को समझने के लिए चीफ जस्टिस की अदालत में चल रहे दूसरे मुकदमों का हाल जानना जरूरी है।

स्वच्छ जल जीवन है, पर बिगड़े तो हाहाकार है



विश्व जल दिवस विशेष 22 मार्च 2025

प्रदूषक, रेडियोधर्मी कचरे, थर्मल प्रदूषण, मानव अपशिष्ट, औद्योगिक उद्यम, ऑयल पॉल्यूशन, कृषि प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, खनन, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, अम्ल वर्षा जैसे कारण विशेष है, पानी के संपर्क में आते ही यह विशेष कारण जल को विषैला बना देते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2021 में 2 बिलियन से ज्यादा लोग पानी की कमी वाले देशों में रहते थे। 2022 में, वैश्विक स्तर पर कम से कम 1.7 बिलियन लोग मल से दूषित पेयजल स्रोतों का उपयोग करते थे। मल संदूषण के कारण पेयजल में सूक्ष्मजीवों का संदूषण, पेयजल सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। 2021 में, 251.4 मिलियन से अधिक लोगों को सिरटोसोमियासिस के लिए निवारक उपचार की आवश्यकता थी। सूक्ष्मजीवीय रूप से दूषित पेयजल से डायरिया, हैजा, पेचिश, टाइफाइड और पोलियो जैसी बीमारियां फैल सकती हैं, तथा अनुमान है कि इससे हर साल डायरिया से संबंधित लगभग 505,000 मौतें होती हैं। 296 मिलियन लोग असुरक्षित कुओं और झरनों से पानी भरते हैं और 115 मिलियन लोग झीलों, तालाबों, नदियों और झरनों से अनुपचारित सतही जल एकत्र करते हैं।

तीव्र शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण जल संसाधनों का प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे वे उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। अकुशल कृषि पद्धतियां, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, भूजल का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, खराब जल प्रबंधन और उचित बुनियादी ढांचे की कमी जैसे कई कारक जल की कमी के संपर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व बैंक के कुछ आंकड़े अनुसार, भारत देश में 163 मिलियन भारतीयों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, 210 मिलियन भारतीयों को बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच नहीं है। 21 प्रतिशत संक्रामक रोग असुरक्षित जल से संबंधित है, भारत में प्रतिदिन पांच वर्ष से कम आयु के 500 बच्चे दस्त से मरते हैं। भारत की आधी से अधिक नदियां अत्यधिक प्रदूषित हैं, तथा कई अन्य नदियां आधुनिक मानकों के अनुसार असुरक्षित स्तर पर हैं। शहरों से बहनेवाली नदियां नालों का स्वरूप धर चुकी हैं। नीति आयोग की 2018 समग्र जल प्रबंधन सुचक्रांक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षित जल की अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग दो लाख लोग मर जाते हैं। 2030 तक लगभग 600 मिलियन लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, जो भारत देश की अनुमानित जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत होगा।

वॉटर गैर-लाभकारी संगठन बताती है कि, भारत देश में 1.4 बिलियन की आबादी में से आज भी 35 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित जल तथा 678 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है, सुरक्षित जल और स्वच्छता की कमी के कारण हर वर्ष दस लाख से अधिक लोग मरते हैं, तथा हर दो मिनट में एक बच्चा जल या स्वच्छता से संबंधित बीमारियों के कारण जान गंवाता है। विश्व के 29 प्रतिशत स्कूलों में स्वच्छ जल और शौचालय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव है। बुनियादी जल और स्वच्छता की कमी के कारण हर वर्ष विश्वभर में 260 बिलियन डॉलर बर्बाद हो जाते हैं। विश्व की कम से कम 50 प्रतिशत जनसंख्या वर्ष में कम से कम एक माह तक अत्यधिक जल संकट में रहते हैं। बुनियाभर में महिलाएं और लड़कियां प्रतिदिन कई किलोमीटर तक पानी के लिए भटकती हैं और पानी इकट्ठा करने में 200 मिलियन घंटे तक बिताती हैं। घर पर सुरक्षित जल और स्वच्छता की उपलब्धता, व्यतीत किए गए समय को बचाती है, जिससे परिवारों को शिक्षा और कार्य के अवसरों को प्राप्त करने के लिए अधिक समय मिलता है, जिससे उन्हें गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद मिलेगी।

जल को जल किसी चीज की कमी न हो, तब तक मनुष्य को उस चीज की कीमत नहीं समझतीं, जल से जीवन है, अधिकतर लोगों को पानी प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके हिसाब से दुनिया में पानी सहज उपलब्ध है, शायद इसलिए पानी का मोल लोग नहीं समझते हैं। किसी कठिन परिस्थिति में अगर पानी न मिलें तो तन-मन व्याकुल हो उठता है, शीम ऋतु के मौसम में शहरों में किसी कारणवश एक दिन भी जनता को पानी न मिलें तो हाहाकार मच जाता है, तब दुनिया की सबसे कीमती चीज पानी लगती हैं। आज जो पानी हमें सहज उपलब्ध हो रहा है, करोड़ों लोग उस पानी के लिए रोज दर-दर भटकते हैं, अपना कीमती समय पानी इकट्ठा करने में गवाते हैं, फिर भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल नसीब नहीं होता, मजबूरी में अशुद्ध जल के उपयोग के कारण घातक बीमारियों का शिकार होकर असमय मौत के आगोश में चले जाते हैं। पानी की कमी के कारण यशु-पक्षियों, वन्यजीवों का तो अधिक बुरा हाल होता है। पानी का अपव्यय और योग्य प्रबंधन द्वारा संभ्रमण, इसके तरीके हम सभी जानते हैं, लेकिन गंभीरता नहीं समझते। अनमोल पानी का महत्व समझें, शुद्ध जल पर प्रत्येक व्यक्ति और जीवों का बराबरी का अधिकार है, सबको शुद्ध जल मिलें यह हम सबकी जिम्मेदारी हैं। जल बचाएं, अनमोल जीवन बचाएं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

किसान आंदोलन : विरोध की राह से भटकाव तक का सफर

लोकतंत्र का असली सौंदर्य उसकी आजादी में छिपा है-वह आजादी जो हर नागरिक को अपनी बात कहने, अपनी असहमति जताने का हक देती है। यह अधिकार ही लोकतंत्र की धड़कन है, जो सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है और शासन को निरंकुश होने से रोकता है। लेकिन जब यही विरोध अपनी सीमाएं लांघकर तर्क और समाधान की राह छोड़ देता है, जब वह हठधर्मिता और टकराव का रंग ले लेता है, तो वह न केवल अपने मकसद से भटक जाता है. बल्कि समाज के लिए बोझ बन जाता है। किसान आंदोलन इसका सबसे ज्वलंत और दुखद उदाहरण है। यह आंदोलन, जो कभी किसानों की आवाज बनकर उभरा था, धीरे-धीरे संवाद की संभावनाओं को कुचलता हुआ अड़िखलपन और अव्यवस्था का पर्याय बन गया। इसने न सिर्फ कृषि सुधारों के सवाल को उलझाया, बल्कि देश के सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न किया और आर्थिक ढांचे को ठप कर दिया। सवाल यह है-यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, और कहाँ जाकर भटक गया? किसान आंदोलन की शुरुआत 2020 में तब हुई, जब केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को लाू किया। सरकार का दावा था कि ये कानून किसानों को बिचौलियों की जकड़न से आजादी देंगे, उन्हें खुले बाजार में अपनी उपज बेचने का मौका देंगे, और खेती को आधुनिक बनाकर उनकी आय बढ़ाएंगे। यह एक बड़ा सपना था—कृषि को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने का सपना। लेकिन किसानों के मन में शंकाएं उपनपने लगीं। क्या ये कानून बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए रास्ता बनाएंगे? क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था, जो दशकों से उनकी आर्थिक रीढ़ रही है, खत्म हो जाएगी? ये डर जायज थे, क्योंकि भारत जैसे देश में खेती सिर्फ आजीविका नहीं, संस्कृति और भावनाओं का हिस्सा है। किसानों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज

बुलंद की, और शुरुआत में यह विरोध एक सशक्त लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रूप में उभरा। सरकार ने इन शंकाओं को दूर करने की कोशिश की। कई दौर की वार्ता बुलाई गईं, कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी बनाकर बीच का रास्ता निकालने की पहल की। लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनकी जिद थी कि कानून पूरी तरह रद्द हो और एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले। यह अड़ियल रुख धीरे-धीरे संवाद की हर गुंजाइश को निगल गया। दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैक्टरों की कतारें लगीं, सड़कें महीनों तक जाम रहीं, ट्रकों की लंबी लाइनें ठहर गईं, व्यापार ठप हुआ, और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। यह आंदोलन अब किसानों की लड़ाई से ज्यादा हठधर्मिता का प्रदर्शन बन चुका था। क्या यह वाकई किसानों के हित में था, या सिर्फ एक ऐसी जिद जो समाधान की बजाय समस्या को और गहरा रही थी? किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। पहली नजर में यह मांग भावनात्मक रूप से मजबूत और जायज लगती है। आखिर कौन किसान नहीं चाहेगा कि उसकी फसल का दाम तय हो, उसकी मेहनत की कीमत सुरक्षित रहे? लेकिन इस मांग का दूसरा पहलू उतना ही जटिल और चुनौतीपूर्ण है। अगर एमएसपी को कानून बना दिया जाए, तो सरकार को हर फसल को तय दाम पर खरीदना होगा—चाहे बाजार में उसकी मांग हो या न हो। इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, गोदामों में अनाज सड़ेगा, और कृषि बाजार का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इनामा ही नहीं, इससे किसानों में नवाचार की भावना कम होगी—नई फसलें उगाने, तकनीक अपनाने या बाजार की जरूरतों के हिसाब से बदलने की प्रेरणा खत्म हो जाएगी। सरकार ने इन खतरों को बार-बार सामने रखा, इसे अन्यावहारिक बताया, लेकिन आंदोलनकारियों के कानों पर जूं तक न रंगी। यह हठ क्या हासिल कर रहा था-किसानों का भला, या सिर्फ एक असंभव सपने की खोज?

इस पूरे प्रकरण में पंजाब सरकार की भूमिका भी कम दिलचस्प नहीं। जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे थे, तब सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने खुलकर उनका साथ दिया। उनके नेता धरना स्थलों पर पहुंचे, जोशीले भाषण दिए, और किसानों को 'क्रांतिकारी' करार दिया। यह समर्थन तब तक चला, जब तक आंदोलन से अराजकता नहीं फैली।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

फेसबुक वॉल से



एक्स से



आज का दोहा

जग बदला ना, मैं कभी, बदले ना सरकार।

जब भी मांगी जिंदगी, मिलती रही उधार।।

सोमदत्त शर्मा, गाजियाबाद (उ.प्र.)

रचना भेजिए

समाचारों के संबंध में शिकायत या इस पेज के लिए

आर्टिकल कृपया भेजें artical.rnmail@gmail.com

कॉल/व्हाट्सएप 8292553444

संपादक

क्या ‘प्रधान पति’, ‘मुखिया पति’ ‘सरपंच पति’ की होगी छुट्टी?

आधी आबादी की भागीदारी के बिना विकसित भारत का स्वप्न संभव नहीं है। महिलाएं देश की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लें, इसके लिये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में उनकी भागीदारी आरक्षण के द्वारा सुनिश्चित की गई। आज 33 से 50 फीसदी तक महिला आरक्षण राज्यवार दिया गया है। इसका उद्देश्य साफ था कि अंतिमजननों की आवाजों को प्रमुखता से सुनना। पर व्यवस्था की खामियों का क्या किया जाए, ये अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। आज इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक बड़ी समस्या ‘प्रधान पति’, ‘मुखिया पति’, ‘सरपंच पति’ बने हुए हैं। हालिया रिपोर्ट में भी यह समस्या उजागर की गई है कि कैसे महिला सरपंच के पुरुष प्रतिनिधि उनकी जगह पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है।

पिछले दिनों पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पूर्व खान सचिव सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित समिति ने एक रिपोर्ट मंत्रालय को पेश की है। इस समिति का गठन सितंबर, 2023 में किया गया था। ‘पंचायती राज प्रणालियों और संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं को बदलना: प्रॉक्सी भागीदारी के प्रयासों को खत्म करना’ शीर्षक वाली यह रिपोर्ट प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की बात जोर-शोर से उठाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गांवों में महिलाओं की पारंपरिक और सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक मानसिकता और कठोर सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों को मनवाने से भी महिला प्रतिनिधित्व पीछे चला जाता है। इसमें एक है कई तरह की पदों प्रथाओं का पालन करना। रिपोर्ट में एक कारण राजनीतिक दबाव को भी बताया गया है, जिसमें राजनीतिक विरोधियों द्वारा मिलने वाली धमकी और दबाव भी है जिसे न मानने पर उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियों के कारण उन्हें सार्वजनिक कामों से खुद को अलग करने का दबाव भी रहता है। घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों के दबाव में वे अक्सर घर की जिम्मेदारी को चुन लेती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा कारण उनका अशिक्षित रह जाना भी है। बहुत-सी सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं को शिक्षा और सार्वजनिक कामों के अनुभव न हो पाने के कारण वे निर्वाचित होने के बावजूद अपनी भूमिका

सीमित कर लेती हैं। सबसे ज्यादा उन्हें वित्तीय निर्णय संबंधी कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से वे संबंधित पुरुष साथियों की मदद लेने को मजबूर हो जाती हैं।

स्थानीय शासन में वास्तविक महिला नेतृत्व को मजबूत करने के मंत्रालय के लगातार प्रयासों के पक्ष में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसकी वजह है कि इसमें न केवल वास्तविक समस्या की पहचान की गई है बल्कि समस्या का समाधान भी प्रस्तावित किया गया है। इस कड़ी में मंत्रालय द्वारा साल भर चलने वाला ‘सशक्त पंचायत नेत्री अभियान’ है, जिसे देश भर में पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। यह पंचायती राज पदों पर निर्वाचित महिलाओं के कौशल और आत्मविश्वास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही हैं कि नहीं। इस रिपोर्ट में इस समस्या से निपटने के लिये कुछ सुधारतात्मक दंड की सिफारिशें की गई हैं। ताकि प्रधान पति, सरपंच पति या मुखिया पति की प्रथा पर रोक लगाई जा सके।

देश की पहली एमबीए सरपंच राजस्थान के टोंक जिले से सोदा गांव की छवि राजावत थीं, जो 2010 में सरपंच बनीं और महिला सशक्तिकरण के लिये काम किया था। अपने एक लेख में कहती हैं कि मेरा देश अपवाद हो सकता है आज भी देश में बहुत-सी निर्वाचित महिला सरपंच शिक्षा और प्रशासनिक ढांचे के सामान्य ज्ञान की कमी से जूझ रही हैं। परिणामस्वरूप वे अलग-थलग पड़ जाती हैं। इस कारण उनकी छोड़ी गई जगहों को भरने के लिये जिम्मेदारी को चुन लेती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ा कारण उनका अशिक्षित रह जाना भी है। बहुत-सी सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं को शिक्षा और सार्वजनिक कामों के अनुभव न हो पाने के कारण वे निर्वाचित होने के बावजूद अपनी भूमिका

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

प्लेसमेंट व पैकेज की समस्या से जूझते आज के युवा

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर केवल एक देश की समस्या ना होकर अब वैश्विक समस्या होती जा रही है। रोजगार का लेकर अब तो यह भी बेमानी हो गया है कि आपने कहाँ से अध्ययन किया है। हालात यह होने जा रहे हैं कि दुनिया के श्रेष्ठतक अध्ययन केन्द्रों के पासआउट युवा भी अच्छे पैकेज के रोजगार के लिए दो चार हो रहे हैं। यह कल्पना या कपोल कल्पित नहीं बल्कि वास्तविकता है कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, शिकागो, कोलंबिया, एमआईटी, पेंसिलवेनिया, एमआईटी जैसे वैश्विक ख्यातनाम संस्थानों से एमबीए करें युवाओं को पासआउट के तीन माह बाद तक ऑफर नहीं मिलने की संख्या में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने अमेरिका के सात शीर्ष संस्थानों से एमबीए का अध्ययन कर निकले विद्यार्थियों के प्लेसमेंट को लेकर अध्ययन कर रिपोर्ट में तो यही खुलासा किया है। चौकाने वाली बात यह है कि 2021 की तुलना में 2024 में यह प्रतिशत करीब करीब चार गुणा बढ़ गया है। 2021 में केवल 4 प्रतिशत पासआउट छात्र ही ऐसे थे जिन्हें पासआउट के तीन माह बाद तक ऑफर नहीं मिलता था वह संख्या 2024 तक बढ़कर 15

डॉ. राजेंद्र प्रसाद शर्मा

प्रतिशत हो गई है। अमेरिका के शीर्ष सात संस्थानों में कहीं कहीं तो छह गुणा तक की बढ़ोतरी देखी गई है। यह इसलिए भी चिंताजनक है कि जिन संस्थानों के अध्ययन का रेट्रैडेंट निर्विवाद समूचे विश्व में श्रेष्ठतम रहा है और जिनकी वैश्विक पहचान है उनकी ही यह हालत है तो आम संस्थानों की क्या होगी? यह अकल्पनीय है। हो सकता है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अतिशयोक्तिपूर्ण हो पर हालात जिस तरह के सामने आ रहे हैं उससे यह साफ हो जाता है कि प्लेसमेंट की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। सवाल केवल प्लेसमेंट तक ही सीमित नहीं हैं अपितु पैकेज में भी लगातार कमी देखी जा रही है। कुछ चंद युवाओं को अच्छा पैकेज मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि कंपनियों द्वारा युवाओं को अच्छा पैकेज दिया जा रहा है। दरअसल कोरोना के बाद से प्लेसमेंट और पैकेज को लेकर हालात बहुत हद तक बदल गए हैं। यदि हम भारत की ही बात करें तो देश के शीर्ष प्रबंध संस्थानों से पासआउट युवाओं को 2022 में औसत 29 लाख का पैकेज मिल रहा था तो वह 2024 आते आते 27 लाख पर आ गया है। यह सबतो देश दुनिया के शीर्ष अध्ययन संस्थानों से पासआउट युवाओं को लेकर है। सामान्य व मध्यस्तरीय संस्थानों से पासआउट युवाओं को मिलने वाला पैकेज तो बहुत ही कम होता जा रहा है। दूसरी ओर घर बार छोड़कर 90 घंटे तक काम करने को लेकर बहस चल रही है। एक और पिकोक कल्चर, हाईबीड सिस्टम और वर्क फ्राम होम से कार्यस्थल पर युवाओं को लाने की जद्दोजहद जारी है तो दूसरी ओर कम होते अवसर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। (ये लेखक के निजी विचार हैं।)



